GONZALO CASTRO DE LA MATA
Chairman
The Inspection Panel

IPN REQUEST RQ 18/06

5 नवंबर, 2018

पंजीकरण का नोटिस

निरीक्षण के लिए अनुरोध

भारतः निम्न आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (P132173)

सारांश

1. 21 सितंबर, 2018 को, निरीक्षण पैनल ("पैनल") को निम्न आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (RWSSP) ("परियोजना") के निरीक्षण के लिए एक अनुरोध ("अनुरोध") प्राप्त हुआ। अनुरोध भारत के झारखंड राज्य के एक गांव से संथाल जनजाति समुदाय के 104 सदस्यों ("अनुरोधकर्ता") द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 9 अक्टूबर, 2018 को, अनुरोधकर्ताओं ने कथित नुकसान को स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त विवरणों के साथ अपने अनुरोध का एक पूरक पैनल को भेजा। अनुरोधकर्ताओं ने गोपनीयता बनाए रखने की माँग की है।

2. अनुरोधकर्ता RWSSP ("योजना") के तहत वित्तपोषित योजना के भाग के तौर पर अपने गांव में एक जल शोधन संयंत्र के निर्माण के बारे में चिंतित हैं। वे दावा करते हैं कि यह संयंत्र उनकी उस सामुदायिक भूमि पर बनना है जिसमें एक पैतृक पवित्र बगीचा स्थित होने के कारण संथाल जनजाति के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके साथ ही यह भूमि मृत लोगों को दफन करने और दाह संस्कार के काम आती है। उनका कहना है कि इससे सामुदायिक संसाधनों और औषधीय जड़ी-बूटियों तक उनकी पहुंच समाप्त हो सकती है। वे प्रस्तावित संयंत्र से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों पर, विकल्पों के विश्लेषण की कमी और अपर्याप्त पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन के प्रति चिंता जाहिर करते हैं। अनुरोधकर्ताओं ने स्थानीय भाषाओं में सलाह और सूचना के प्रकटीकरण की कमी बताई है और बदले की कार्रवाई के बारे में चिंता जाहिर की है। उन्होंने पैनल से परियोजना द्वारा उनके जनजातीय समुदाय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का निरीक्षण करने की मांग की है।

3. आरंभिक समुचित सतर्कता प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेंस) पूरी करने और इसकी पुष्टि करने के बाद कि अनुरोध पैनल के स्वीकार्यता मानदंड को पूरा करता है, मैं आपको सूचित करता हूं कि मैंने 5 नवंबर, 2018 को यह अनुरोध पंजीकृत कर लिया है।

परियोजना

4. ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना (P132173) 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है, जिसमें से 500 अमेरिकी डॉलर वित्त इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA) प्रदान करता है और बाकी वित्त भारत सरकार प्रदान करती है। परियोजना 30 दिसंबर, 2013 को स्वीकृत की गई और इसके समाप्त होने की तिथि 31 मार्च, 2020 है।

5. परियोजना का विकास लक्ष्य "विकेंद्रीकृत डिलीवरी व्यवस्था के जरिए लक्षित राज्यों में चुनिंदा ग्रामीण समुदायों के लिए पाइप द्वारा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाओं को उन्नत बनाना तथा भागीदार राज्यों की एक संभावनापूर्ण जोखिम या आपात स्थिति से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटने की क्षमता बढ़ाना है।"[1]

6. परियोजना के चार अंग हैः अंग क) क्षमता निर्माण एवं सेक्टर विकास; अंग ख) ढांचागत विकास; अंग ग) परियोजना प्रबंधन सहायता; और अंग घ) आकस्मिकता आपातकालीन प्रतिक्रिया। अनुरोध का संबंध घटक B से है।

7. परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज (PAD) निर्दिष्ट करता है कि यह अंग "नए ढांचों के निर्माण एवं विद्यमान योजनाओं के पुनरुद्धार एवं संवर्धन सहित, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कवरेज को उन्नत बनाने के लिए निवेश में सहायता करेगा।"[2] PAD के अनुसार, जल आपूर्ति निवेश में जल स्रोतों को विकसित करना और कैचमेंट क्षेत्र की सुरक्षा गतिविधियां शामिल होंगी। जहां अधिकांश स्थानों के स्थानीय भूजल स्रोतों का उपयोग कर एकल ग्राम योजनाओं से लाभान्वित होने की संभावना है, दस्तावेज स्पष्ट करता है कि "मुख्यतः सतही जल स्रोतों पर निर्भर रहते हुए बहु ग्राम योजनाएं (MVS) उन स्थानों के लिए लाई जाएंगी जहां स्थानीय स्रोत या तो दीर्घकालिक नहीं है या स्वीकार्य गुणवत्ता का नहीं है।"[3]

8. परियोजना को पर्यावरणीय श्रेणी बी निर्दिष्ट की गई थी और इसने निम्न सुरक्षा नीतियां शुरू कीः पर्यावरणीय मूल्यांकन (OP/BP 4.01), प्राकृतिक रिहायश (OP/BP 4.04), वन (OP/BP 4.36), मूल निवासी (OP/BP 4.10) और अंतर्राष्ट्रीय वॉटरवेज पर परियोजनाएं (OP/BP 7.50)।

[1] परियोजना मूल्यांकन दस्तावेज, पृ.3.

[2] पूर्वोक्त. पृ.5.

[3] पूर्वोक्त.

अनुरोध

9. अनुरोध भारत के झारखंड राज्य के एक गांव से संथाल जनजाति समुदाय के 104 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि "[उनके गांव के] मूल निवासियों की जीवन पद्धति "जल शोधन संयंत्र के स्थान से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है" और कि "पहाड़ी को उनसे छीन लेना समुदाय की संस्कृति और आर्थिक स्थायित्व को खतरा पहुंचाता है।" उन्होंने निम्न नुकसानों का आरोप लगाया है।

10. **सांस्कृतिक प्रभाव।** अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि परियोजना ने मूल निवासियों पर पड़ने वाले प्रभावों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है जोकि OP 4.10 का गैर-अनुपालन (नॉन-कम्प्लायंस) है। वे आरोप लगाते हैं कि जल शोधन संयंत्र का निर्माण उनकी सामुदायिक भूमि पर किया जा रहा है, जिसका संथाल मूल निवासी समुदाय के लिए पीढ़ियों से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अनुरोधकर्ता दावा करते हैं कि उनके गांव की सीमा पर, जहां संयंत्र का निर्माण हो रहा है, एक पवित्र बगीचा है जहां आत्माएं बसती हैं। वे बताते हैं कि इस पवित्र बगीचे में समुदाय *जंताड़ पूजा* कहलाने वाली एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के तहत पूजा-अर्चना करता है, और इस स्थान पर अनेक त्योहार आयोजित होते हैं। आयोजकों का यह भी कहना है कि जल शोधन संयंत्र का निर्माण एक ऐसी पहाड़ी पर हो रहा है जिस पर "बहुत पुराने समय से" समुदाय का कब्रिस्तान और दाह-संस्कार का स्थान है। वे तर्क देते हैं कि परियोजना को भौतिक सांस्कृतिक संसाधन नीति लागू करनी चाहिए और कि भौतिक सांस्कृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित मूल्यांकन और राहत के उपायों का अभाव, OP 4.11 का गैर-अनुपालन दर्शाता है। अनुरोधकर्ता कहते हैं कि प्रभावित पहाड़ी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रभावित झाड़ियां और जड़ी-बूटियां समुदाय द्वारा पारंपरिक उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि पहाड़ी पर पाई जाने वाली लाल मिट्टी उनके घरों की रंगाई, सफाई और सामान सुरक्षित रखने में काम आती है।

11. **आजीविका पर प्रभाव।** अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि पहाड़ी पर उगने वाली सब्जियों का समुदाय द्वारा उपभोग किया जाता है और पेड़-पौधे घरों में ईंधन के रूप में और घर के बगीचे की बाड़ लगाने के उपयोग में आते हैं। उनका यह भी दावा है कि प्रभावित पहाड़ी उनकी बकरियों के लिए चरागाह के रूप में उपयोग की जाती थी, लेकिन संयंत्र के निर्माण से इस भूमि पर उनकी पहुंच बाधित हुई है। अनुरोधकर्ता कहते हैं कि वर्तमान में उन्हें मुफ्त में जल उपलब्ध है और वह जल उपभोग के लिए उचित है। वे दावा करते हैं कि योजना ने "पेयजल के लिए [उनसे] पैसा वसूलकर [उनके] पहले से ही गरीबी से ग्रस्त समुदायों को और अधिक असुरक्षित किया है।"

12. **मूल निवासियों के लिए वैधानिक संरक्षण।** अनुरोधकर्ता कहते हैं कि, एक मूल निवासी-बहुल क्षेत्र के रूप में, उनके गांव को राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत विशेष सुरक्षा प्राप्त है, जिसे कोई भी विकास योजना

लागू करने और सामुदायिक भूमि से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए *ग्राम सभा* [4] की सहमति की आवश्यकता है। वे आरोप लगाते हैं कि वर्तमान स्थान पर जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए संबंधित ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई और इसलिए यह योजना असंवैधानिक है।

13. अनुरोधकर्ता चिंता जाहिर करते हैं कि योजना नजदीकी शहर की सीमाओं को विस्तारित करने और उनके मूल निवासी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वे कहते हैं कि इससे क्षेत्र की प्रकृति को नुकसान पहुंच सकता है और भारत में एक गांव के तौर पर उनके समुदाय को प्राप्त होने वाले वैधानिक संरक्षणों को समाप्त कर सकता है, और इस प्रकार उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेल सकता है।

14. **परामर्श।** अनुरोधकर्ताओं का आरोप है कि उनके गांव में सहमति के लिए कोई मीटिंग आयोजित नहीं हुई और "समुदाय से [योजना] के किसी भी पहलू के बारे में बात नहीं की गई।" उनका कहना है कि समुदाय के अधिकांश सदस्यों को परियोजना के बारे में इसके शुरू होने से एक माह पहले तब पता चला जब स्थानीय प्रशासन पुलिस बल के साथ पड़ोस के गांव में आया। वे स्पष्ट करते हैं कि इसे सहमति नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका उद्देश्य "कथित तौर पर जल शोधन संयंत्र के लिए ग्रामीणों का पवित्र बगीचा उपयोग करने के लिए उनकी सहमति देने पर बाध्य करना था।" अनुरोधकर्ताओं का यह भी आरोप है कि अन्य गांवों में उनके गांव की स्त्रियां किसी प्रकार के सम्मति में शामिल नहीं हुईं। वे कहते हैं कि स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के अभाव से OP 4.10 का गैर-अनुपालन निर्धारित होता है।

15. **सूचना का प्रकटीकरण।** अनुरोधकर्ता दावा करते हैं कि उन्हें उनकी भाषा में योजना से संबंधित उचित सूचना प्रदान नहीं की गई। उनके अनुसार, दस्तावेज अंग्रेजी में थे, लेकिन हिंदी या संथाली में नहीं। अनुरोधकर्ता स्पष्ट करते हैं कि सूचना के अधिकार का दावा करने के बाद उन्हें कुछ परियोजना दस्तावेज प्राप्त हुए लेकिन उन्हें इसके लिए संबंधित खर्चे करने पड़े और उन्हें योजना के लिए पर्यावरणीय या सामाजिक मूल्यांकन प्रदान नहीं किया गया।

16. **बदले की कार्रवाई।** अनुरोधकर्ता दावे के साथ कहते हैं कि जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, पुलिस अफसरों ने मजदूरों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन पर बल प्रयोग किया। उनका आरोप है कि समुदाय के जिन सदस्यों ने बीच-बचाव की कोशिश की, उन्हें पीटा गया और अनेक ग्रामीणों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। अनुरोधकर्ता दावा करते हैं कि विरोध करने वाले समुदाय के अनेक सदस्यों पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब उन्हें पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जोकि भारत में रोजगार पाने सहित विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है।

[4] ग्राम सभा एक विचारात्मक निकाय है जिससे गांव का हर निवासी जुड़ा होता है, जिसकी समय-समय पर सभा होती हैं और जिससे बजट आवंटन, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चुनाव, और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस, विमर्श करने की अपेक्षा की जाती है।

17. **परियोजना विकल्प और पर्यावरणीय मूल्यांकन।** अनुरोधकर्ता योजना के स्थान पर सवाल करते हैं क्योंकि उनका दावा है कि पहले ही से शुद्ध जल तक उनकी पहुंच है। उनका यह भी आरोप है कि परियोजना ने परियोजना विकल्पों का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जिससे प्रतिकूल प्रभाव कम होते और पर्यावरण को बचाने की संभावना बढ़ती। अनुरोधकर्ता तर्क देते हैं कि समूचे झारखंड के लिए केवल एक बुनियादी पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन तैयार किया गया और विशेषकर इस योजना के लिए कोई विशेष पर्यावरणीय या सामाजिक मूल्यांकन नहीं किया गया। वे चिंता जाहिर करते हैं कि यह योजना पास की नदी से काफी मात्रा में जल का दोहन करेगी, जिससे मूल निवासियों के जल प्राप्त करने को प्रभावित करेगी। वे योजना के संचयी जल विज्ञान संबंधी प्रभावों के साथ ही अन्य योजनाओं के बारे में भी चिंता जाहिर करते हैं जो आसपास के क्षेत्र में परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित की गई हैं। अनुरोधकर्ता गाद प्रबंधन के बारे में सूचना की कमी और संभावित विषैले संदूषण की शिकायत करते हैं। अंत में, वे दावा करते हैं कि परियोजना श्रेणी ए के स्थान पर श्रेणी बी को गलत ढंग से निर्दिष्ट किया गया है।

आरंभिक समुचित सतर्कता (इनीशियल ड्यू डिलीजेंस)

18. अनुरोध प्राप्त होने के बाद, पैनल ने अपनी आरंभिक समुचित सतर्कता प्रक्रिया की और जांचा कि क्या अनुरोध पंजीकरण के लिए स्वीकार्यता मानदंड को पूरा करता है, जो निम्न हैः

19. अनुरोध अगंभीर, निरर्थक या अज्ञात नहीं है, और भारत के झारखंड राज्य में, जहां परियोजना स्थित है, एक गांव के संथाल जनजाति समुदाय के 104 सदस्यों ने इसे प्रस्तुत किया है।

20. अनुरोधकर्ताओं ने बैंक प्रबंधन के साथ 6 अप्रैल, 2018 को हुए पिछले पत्र व्यवहार का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने परियोजना के बारे में चिंताएं जाहिर की हैं। अनुरोधकर्ताओं के अनुसार, प्रबंधन ने उनका ईमेल प्राप्त किया और शिकायत को परियोजना क्रियान्वयन इकाई को अग्रेषित करने का वादा किया। अनुरोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने प्रबंधन को यह बताते हुए कि उनकी चिंताओं के बारे में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, 10 जून, 2018 को एक और ईमेल किया। अनुरोधकर्ताओं ने इंगित किया कि 6 अक्टूबर, 2018 को उन्हें प्रबंधन की तरफ से एक प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने पैनल को शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें प्रबंधन की प्रतिक्रिया अनुचित लगी और उठाए गए मुद्दों का कोई हल नहीं निकला।

21. पैनल ने इसकी भी जांच की कि अनुरोध का विषय सरकारी खरीद से संबंधित नहीं है और, अनुरोध प्राप्ति के समय, परियोजना की 21.68 प्रतिशत राशि दी जा चुकी थी। परियोजना समाप्ति की तिथि 31 मार्च, 2020 है। पैनल ने इस अनुरोध में उठाए गए मुद्दों पर एक अनुशंसा भी नहीं दी है।

22. पैनल ने 3 अक्टूबर, 2018 को और 1 नवंबर, 2018 को पुनः उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुरोधकर्ताओं से फोन पर बात की। उन्होंने कथित नुकसानों के बारे में विवरण उपलब्ध कराए और पैनल से परियोजना का तुरंत निरीक्षण करने की प्रार्थना की।

23. पैनल 29 अक्टूबर, 2018 को बैंक प्रबंधन से मिला। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने परियोजना क्षेत्र में एक अभियान आयोजित किया था और पैनल द्वारा 4 अक्टूबर, 2018 को अनुरोध प्राप्त होने का नोटिस जारी करने के बाद समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि वे अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

अनुरोध का पंजीकरण

24. IDA प्रस्ताव ("प्रस्ताव") के पैराग्राफ 17 के अनुसार जिसने पैनल को स्थापित किया है, "पैनल का अध्यक्ष निरीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत प्रबंधकारी निदेशकों और बैंक के अध्यक्ष को सूचित करेगा।"[5] इस नोटिस के साथ, मैं आपको सूचित करता हूं कि मैंने, 5 नवंबर, 2018 को, यह अनुरोध पंजीकृत किया।

25. निरीक्षण के अनुरोध के गुणों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय पैनल के पंजीकरण में निहित नहीं है। प्रस्ताव के पैराग्राफ 18, और "निरीक्षण पैनल के बोर्ड की दूसरी समीक्षा के निष्कर्ष" ("1999 स्पष्टीकरण") के पैराग्राफ 2 और 8 के अनुसार, बैंक प्रबंधन को निरीक्षण के अनुरोध में उठाए गए मुद्दों के लिए 21 कार्यदिवसों (6 दिसंबर 2018) के भीतर पैनल को प्रतिक्रिया देनी होगी। बैंक को अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया में जिस विषय को अवश्य संबोधित करना है वे 1999 स्पष्टीकरण के पैराग्राफ 3 और 4 में बताए गए हैं।

26. प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, पैनल, जैसा कि 1999 स्पष्टीकरण और प्रस्ताव के पैराग्राफ 19 द्वारा निर्दिष्ट है, "तय करेगा कि क्या अनुरोध [प्रस्ताव के] पैराग्राफ 12 और 14 में बताए गए पात्रता मानदंड को पूरा करता है और प्रबंधकारी निदेशकों को इस बारे में अनुशंसा करेगा कि क्या मामले की जांच की जानी चाहिए।"[6] इस अनुरोध को IPN अनुरोध संख्या RQ 18/06 निर्दिष्ट की गई है।

आपका,

गोंज़ेलो कास्त्रो द ल मात
चेयरमैन

संलग्नक

[5] पैनल को स्थापित करने वाला प्रस्ताव (22 सितंबर, 1993), प्रस्ताव संख्या. IDA 93-6, http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelMandateDocuments/Resolution1993.pdf
[6] पूर्वोक्त.

मि. जिम योंग किम, प्रेसीडेंट
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन

प्रबंधकारी निदेशक एवं विकल्प
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन

(निरीक्षण पैनल और प्रबंधन दस्तावेजों के अनुवाद अनौपचारिक हैं और इच्छुक पार्टियों को सेवा के रूप में प्रदान किए जाते हैं। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। यदि हिंदी में अनुवाद का कोई भी हिस्सा अंग्रेजी में मूल पाठ के साथ असंगत है, तो अंग्रेजी अनुवाद प्रबल होगा।)